© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 04 , Issue : 10 | October – December 2017

कश्मीर के सन्दर्भ में भारत-पाक संबंधों का अध्ययन

Suman Khatri, Assistant Professor, Department of Pol. Science
Saini co-Education College Rohtak

ISSN : 2348-5612 © URR

सन् 1947 के पूर्व पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था पर देश की आजादी के साथ भारत का विभाजन भी हो गया तथा विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं से ही दोनों देशों में शत्रुता भी प्रारम्भ हो गया।अब तक दोनों देशों के मध्य छोटे-बड़े कुल चार युद्ध हो चुके हैं लेकिन लेकिन सभी समस्याएं पूर्वत बनी हुयी हैं।

शत्रुता का उदभव व विकास :-

15 अगस्त 1947 तक सभी देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान में विलय हो चुकी थी लेकिन तीन रियासतें अभी भी स्वतन्त्र थी। इन रियासतों के विलय में सबसे बड़ा अड़पेच कश्मीर को लेकर था क्योंकि कश्मीर के डोगरा राजा हरि सिंह न तो इसे पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे और न ही भारत में विलय।भारत इस मामले में चुप था लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को हर हाल में पाना चाहता था इसलिए पहले तो उसने कश्मीर पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिया क्योंकि उस समय कश्मीर का ज्यादातर व्यापार पाकिस्तान से ही होता था जो की भौगोलिक रूप से सुविधाजनक था लेकिन इस प्रतिबन्ध का राजा हरिसिंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते देख पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली (किराये के आदिवासी सैनिक) आक्रमण करा दिया।कबायलियों ने कश्मीर में कत्लेआम शुरू कर दिए । कश्मीर की सुरक्षा के लिए राजा हरिसिंह ने भारत से सहायता मांगी।भारतीय नेता नेहरू और पटेल सहायता देने के पक्ष में थे लेकिन गवर्नर जनरल माउन्टबेटन अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर यह कहा की जब तक कश्मीर का भारत में विलय नहीं हो जाता तब तक हम कश्मीर की सहायता नहीं कर सकते अतः मजबूर होकर कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अक्सेशन(विलय पत्र)पर हस्ताक्षर कर दिए। अतः शीघ्र ही भारतीय सेना हवाई मार्ग से कश्मीर भेजी गयी। भारतीय सेना को कश्मीर से कबायलियों को पीछे भगाने में सफलता मिल रही थी । कुछ और दिनों में भारतीय सेना कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से पूर्णतया मुक्त करा पाती लेकिन इसी समय नेहरू जी मामले को यू एन ओ में ले गए । यू एन ओ मामले में हस्तक्षेप करके युद्ध विराम समझौता करा दिया।उस समय जितना भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में था आजतक पाकिस्तान के कब्जे में बना हुआ है जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है तथा भारत पाक अधिकृत कश्मीर।

हलाकि इस मामले को सुलझाने के लिए UNO ने एक आयोग का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट में यह प्रस्ताव था की पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना को वापस ले तो वहाँ जनमत संग्रह कराया जायेगा लेकिन पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर से सेना वापस लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसको इस बात का भय था की शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में बहुसंख्यक मुस्लिम भारत के पक्ष में मत व्यक्त करेंगे जिससे उसकी पराजय निश्चित थी।

अतः पाकिस्तान की हठधर्मिता के कारण कश्मीर समस्या आज तक बनी हुयी है जो भारत-पाक संबंधों में खटास का प्रमुख कारण है।

कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान के तर्क :-

1- चूँकि भारत का विभाजन द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था अतः मुस्लिम बहुल कश्मीर पर पाकिस्तान का हक़ है।इसी आधार पर भारत ने जूनागढ़ व हैदराबाद का बल पूर्वक विलय किया था।

2- भौगोलिक रूप से कश्मीर पाकिस्तान के ज्यादा करीब है।स्वतंत्रता से पूर्व कश्मीर का ज्यादातर व्यापार पाकिस्तान वाले क्षेत्र से ही होता था।

3- बिना जनमत संग्रह के कश्मीर का भारत में विलय अवैध है।

4- कश्मीरी जनता आज भी भारत से आजाद होना चाहती है।वह भारतीय झंडे के नीचे नहीं रहना चाहती है।

भारत के तर्क :-

1- कश्मीर का भारत में विलय पूर्णतया वैधानिक है ।भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान था की किस रियासत के किसके साथ सामिल होना है यह रियासत के शासक को निर्णय लेना था। और जब राजा हरीसिंह ने कश्मीर का भारत में विलय कर दिया है तो अब पाकिस्तान का कोई भी तर्क बेबुनियाद है।

2-द्वि-राष्ट्र का सिद्धांत पाकिस्तान की अपनी बुद्धि की उपज है जिसे शासक मानने के लिए बाध्य नहीं होते।

3- जनमत संग्रह की पूर्व शर्त थी की पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना वापस ले।जब उसने पहली शर्त मानने से इंकार कर दिया तो अब जनमत संग्रह का राग अलापने का कोई औचित्य नहीं है।

4- जम्मू कश्मीर की निर्वाचित संविधान सभा ने विधिवत प्रस्ताव पारित करके कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार कर लिया है तथा कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है।

भारत पाक युद्ध 1965 :-

भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग की आधारशिला शायद 1947 में आजादी के समय ही तैयार हो गई थी। उस समय कई मुद्दों के बीच ही कश्मीर भी दोनों देशों के बीच बड़ा मुद्दा था, जो इस युद्ध के विवाद की वजह था। कश्मीर विवाद से अलग गुजरात में मौजूद कच्छ के रण की सीमा भी उस समय विवादित थी। इस सीमा पर पाक ने जनवरी 1965 से गश्त शुरू की थी। इसके बाद यहां पर एक के बाद एक दोनों देशों के बीच आठ अप्रैल से पोस्ट्स को विवाद शुरू हो गया। उस समय के ब्रिटिश पीएम हैरॉल्ड विल्सन ने दोनों देशों के बीच इस विवाद को सुलझाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। इस विवाद को खत्म करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। विवाद सन 1968 में जाकर सुलझा लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों के बीच जंग हो गई।

भारत पाक युद्ध 1971 :-

भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद दोनों देशों ने भारी नुक्सान उठाया था और आज भी उन जख्मों का दर्द लोगों को चुभता है। इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी।

पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है भारत ने 1971 की लड़ाई में आजाद कराया था। बांग्लादेश आज यानी 16 दिसंबर को अपना 'विक्ट्री डे' मना रहा है। भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के रूप में शुरू हुआ था। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज़ादी के बाद से ही सही नहीं रहे और आज भी उलझे हुए है। बांग्लादेश आज़ाद होने से पहले वर्तमान पाकिस्तान में बैठी सरकार ही पश्चिमी हिस्से को अपने तरीके से चलाती थी और पूर्वी पाकिस्तान में जनता का बेहद बुरा हाल था। सेना खूब जुल्म करती थी और आम जनमानस को खूब कुचला जाता था। जब इस पूर्वी पाकिस्तान में विरोध स्वर उठने लगा तो भारत ने इस विरोध का समर्थन किया।सामरिक दृष्टि से भारत के लिए ये फायदे का सौदा था की पूर्वी पाकिस्तान नया देश बन जाए। क्योंकि इससे भारत को पाकिस्तान से होने वाले दो तरफ के खतरे से निजात मिल सकती थी। जब साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन होने लगे तो इन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने फौज को इनका दमन करने के आदेश दिए। पूर्वी पाकिस्तान के लोग चाहते थे की बांग्लादेश इस चंगुल से निकलकर आज़ाद हो। भारत की सेना ने इसमें बांग्लादेशियों का साथ दिया और इस वजह से भारत पाकिस्तान की सेनाएं एकबार फिर आमने सामने आ खड़ी हुई। आखिरकार पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इस लड़ाई के बाद बांग्लादेश तो आजाद हो गया पर इस वार में पाकिस्तानी सेना ने ने करीब 30 लाख लोगों का कत्लेआम किया था। वहीं, इस दौरान फौज ने दो लाख महिलाओं से रेप किया था। लाखों बच्चों को भी मौत के घाट भी उतार दिया गया था।

कारगिल का युद्ध 1999 :-

कारगिल युद्ध वही लड़ाई थी जिसमे पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, भारतीय सेनाओं ने इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना तथा मुजाहिदीनों के रूप में उसके पिठुओं को परास्त किया | कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के जरिये घुसपैठ करने की साजिश के पीछे तत्कालीन पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ को जिम्मेदार माना जाता है | मई 1999 में एक लोकल ग्वाले से मिली सुचना के बाद बटालिक सेक्टर में ले. सौरभ कालिया के पेट्रोल पर हमले ने उस इलाके में घुसपैठियों की मोजुदगी का पता दिया, शुरू में भारतीय सेना ने इस घुसपैठ को जिहादी समझा और उन्हें खदेड़ने के लिए कम संख्या में अपने सैनिक भेजे | लेकिन प्रतिद्वंदियों की और से हुए जवाबी हमले और एक के बाद एक इलाकों में घुसपैठियों की मौजूद होने की खबर के बाद भारतीय सेना को समझने में देर नहीं लगी की असल ले यह एक योजनाबद्ध ढंग से बड़े स्तर पर की गई घुसपैठ थी जिसमे केवल जिहादी नहीं पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी | यह समझ में आते ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया जिसमे 30,000 भारतीय सैनिक शामिल थे |

कारगिल युद्ध का अंजाम :-

दो महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था और आख़िरकार 26 जुलाई को आखरी चोटी पर भी विजय पा ली गयी, यही दिन अब '**कारगिल विजय दिवस**' के रूप में मनाया जाता है |

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पाकिस्तान से विदेशनीति :-

2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशिया की यात्रा के बहाने विदेश सचिव को इस्लामाबाद भेजकर, उफा और उसके बाद पेरिस जलवायु सम्मेलन में नवाज शरीफ से मुलाकात कर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) को पाकिस्तानी एनएसए के साथ मुलाकात करने के लिए बैंकॉक भेजकर पाकिस्तान से संबंध सामान्य करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए। दिसंबर 2015 के आरंभ में भारत और पाकिस्तान समग्र द्विपक्षीय वार्ता एक बार फिर आरंभ करने के लिए सहमत हो गए। उसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन पर बधाई देने तथा उनकी नवासी के विवाह पर शुभकामनाएं देने के लिए अचानक लाहौर में उतरकर सभी को हैरत में डाल दिया।

लेकिन नया वर्ष आरंभ होने से एक दिन पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सरकार के घात और धोखेबाजी भरे दुस्साहस ने उन लोगों को छोड़कर सभी को सदमे में डाल दिया, जो लोग उसकी सभी हरकतों को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में अशांति भड़काने और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की जो कोशिश की थी, उससे दोनों के संबंधों में दरार बहुत बढ़ गई। उसके बाद संबंध बिगड़ते ही रहे और अंत में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सर्जिकल स्ट्राइक हुए और गोलीबारी भी की गई। बहुत दरार आई। भारत ने इसके साथ ही पाकिस्तान को अलग-थलग करने का कूटनीतिक अभियान भी चला दिया और सिंधु जल समझौते जैसे बिना हथियार के उपायों पर पुनर्विचार भी आरंभ कर दिया, जिससे पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता था।

पाकिस्तान की चालबाजियां :-

बाहर से तो पाकिस्तान की स्थिति बेहतर लग रही है, लेकिन भीतर भारत के साथ संबंध सुधारने की इच्छा नजर नहीं आ रही है। सेना भारत के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के खिलाफ ही है। जनमत भी भारत के पक्ष में नहीं है। इसका मतलब है कि असैन्य सरकार चाहे भारत के साथ संबंध सुधारने के पक्ष में रही हो - और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि जमीनी स्थितियां देखने पर ऐसी इच्छा नजर नहीं आती - ताकतवर सेना और विरोध में खड़ी जनता वैसा होने नहीं देगी। ऐसा न हो तो भी असैन्य सरकार कूटनीतिक स्तर पर भारत के खिलाफ जहरीले दुष्प्रचार के अभियान में सबसे आगे रही है - पाकिस्तान में आतंकवाद में भारत के शामिल होने के 'सबूत' वाला एक और 'पुलिंदा' ताजा उदाहरण है - और उसने ऐसे कई मोर्चे खोल दिए हैं, जहां से वापस लौटना उसके लिए मुश्किल होगा। किसी भी सूरत में नवाज शरीफ का खेमा यही सोचता है कि वह 1990 के दशक की नीति पर चल सकता है, जिसमें बातचीत और शत्रुता (जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आतंकवाद का निर्यात था) एक साथ चलते रहते थे।

यह स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान इन बड़े भ्रमों और कल्पनाओं से मुक्त नहीं होता तब तक किसी भी स्तर पर उसके साथ बातचीत करना बेकार ही होगा और पाकिस्तान को उसके घटिया व्यवहार के लिए पुरस्कार देने जैसा होगा। घरेलू राजनीति को भारत की पाकिस्तान नीति में शामिल नहीं होने देना और भी महत्वपूर्ण है। चुनाव को ध्यान में रखकर पाकिस्तान के करीब जाना या उसके खिलाफ जाना भी बड़ी गलती होगी और इससे भारत की पाकिस्तान नीति में से दृढ़ निश्चय का वह भाव खत्म हो जाएगा, जो विरोधी को

साफ दिखना चाहिए। उसके बजाय इससे विनाशकारी हताशा पसर जाएगी, जो भारत की विश्वसनीयता के लिए बहुत घातक साबित होगी।

जो स्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए यह लगभग स्पष्ट है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी पहल से निराशा ही हाथ लगेगी, इसलिए इससे बचना चाहिए। यही समय है, जब पाकिस्तान के नजरिये में या भारत को शत्रु मानने की उसकी धारणा में किसी तरह का बदलाव नहीं आने पर भी उसके साथ शांति को संभव मानने की गलती बार-बार दोहराने की 69 वर्ष लंबी नीति छोड़ दी जाए।

संदर्भ :-

1. नेहरु जवाहरलाल, "भारत की विदेसनिति" प्रष्ट संख्या 79 |
2. अभिनव मिश्रा, "अंतरराष्ट्रीय संबंध", द्रष्टि करैंट अफेयर्स टुडे |
3. जवाहर लाल नेहरु "इंडियाज फारेन पालिसी" : सिलेक्टेड स्पीचेज़, सितेम्बर 1946से अप्रेल 1961 नई दिल्ली 1961 प्रष्ट संख्या 36|
4. अभिनव मिश्रा, , "अंतरराष्ट्रीय संबंध", द्रष्टि करैंट अफेयर्स टुडे, स्वामी मुद्रक एवम प्रकाशक विकास दिव्याकीर्ति मुखर्जी नगर, दिल्ली, दिसम्बर 2015 प्रष्ट 49|
5. यादव आर एस, "भारत की विदेशनीति" डार्लिंग किन्दर्सले (इंडिया) प्रा लि, सेक्टर - 62, नॉएडा, 2013, प्रष्ट - 423|